May I through you, Mr, Chariman, request the hon. Minister to say if there has been a proper study and if so, that study should be made available to us.

MR. CHAIRMAN : This is the question—because of the backwardness of that area.

SHRI AJAY SINGH : There must have been a study, I need notice for this...(*Inerruptions*)...Is he talking about Gandhidham-Bhuj section ?

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : . . (व्यवधान) कच्छ में देखिए।

श्री अजय सिंह वह मुझे खूब पता है। मेरे सामने ही रखी हुई है।

I thought he was talking of the whole of Kutch. As far as Ganchidham-Bhuj section is concerned, a study was made. The first study was made in 1969-70. The Railways again made a study which was conducted in July, 1980 and on both the occasions the length of the project, the cost involved made the project unremunerative. It was picked up again at the request of the Cabinet Committee on Political Affairs in 25-11-1981. There were defence considerations and to line was extended from Bhuj to Nalia.

प्रो० आई० जी० सनदी : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं रेलवे मिनिस्टर श्री जार्ज फर्नान्डीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां कर्णाटक से आदरणीय पोनाचा जी आए और रेलवे मिनिस्टर बने, हनुमनतैया जी आए और रेलवे मिनिस्टर बन गये, टी.ए.पाई जी भी थे, रेलवे मिनिस्टर बन गये, फिर जाफर शरीफ के बाद आप आ गये। मिनिस्टरों का परिवर्तन हुआ है लेकिन कर्णाटक में मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तन नहीं हुआ है, जसे मिरज से बंगलौर लाइन का परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपके जमाने में क्या कर्णाटक में परिवर्तन होगा यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति सवाल भुज के बारे में है, इस पर नहीं है। श्री देवशंकर दवे। आप जल्दी पूछिए समय खत्म होने वाला है।

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : May I know from the Minister what are the norms fixed to convert metre gauge line into broad gauge line ?

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

——

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेलगाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई से अर्जित होने वाले राजस्व में कमी आना

***342. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989–90 के दौरान रेलगाड़ियों से माल की ढुलाई से अर्जित होने वाले राजस्व में कमी आई;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988–89 के दौरान अर्जित किये गये राजस्व के मुकाबले राजस्व में कितनी कमी हुई ;

(ग) क्या सरकार ने राजस्व में उक्त कमी के जिम्मेवार कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरों में जल-निकासी की भूमिगत व्यवस्था के लिए राज्यों को सहायता

*347. श्री अजीत जोगी :
श्री शिव प्रताप मिश्र :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को शहरों में जल निकासी की भूमिगत व्यवस्था के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक दी गई सहायता राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के लिए इस प्रकार की सहायता हेतु मांग की गई थी और यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए अब तक कोई अध्ययन किया है कि महामारी और अन्य संक्रामक रोगों के फैलने के लिए दोषपूर्ण जल-निकासी व्यवस्था किस हद तक जिम्मेदार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

दालों के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन

*348. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी मिशन के कार्य क्षेत्र में दालों के उत्पादन को भी शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रौद्योगिकी मिशन ने दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है और इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस दिशा में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार का तिलहनों संबंधी टैक्नोलाजी मिशन के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है, ताकि दालों के उत्पादन को इसके अंतर्गत लाया जा सके।

तिलहनों संबंधी टेकनोलाजी मिशन ने दालों के विकास के बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आठवीं योजना के दौरान मूल्य प्रोत्साहन, टेक्नोलोजी और आदान सेवाओं के साथ उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम सुझाया गया है। इस पर अन्तर-मंत्रालयी स्तर पर विचार किया जा रहा है जिसके बाद राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

Study on brutality on Child Labour

*349. SHRI SURESH PACHOURI :
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news